

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	विश्व का पहला 'थ्री-वे हाइब्रिड बाजरा' : RHB 273
2.	राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
3.	IICDEM-2026 में राजस्थान के पार्टनर देश - क्रोएशिया एवं कज़ाख़स्तान
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. जामुन, सीताफल व आँवला फ्रूट प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर : उदयपुर 2. 1 फरवरी, 2026 से MedLEaPR सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य 3. राजीविका एवं MNIT जयपुर के मध्य MoU 4. आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 5. राजस्थान इंडस्ट्री एंड SME समिट : जयपुर 6. बालेसर में रेयर अर्थ एलीमेंट्स (REEs) के भंडार 7. सविता माली आर्ट इनोवेशन अवॉर्ड : विजय राही 8. बर्ड फेस्टिवल (उदयपुर)
5.	104वाँ स्कोच शिखर सम्मेलन, 2026
6.	संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे (BBNI) संधि
7.	भारत-UAE संबंध
8.	केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC): ब्रिक्स
9.	दूसरा डॉल्फिन सर्वेक्षण
10.	लक्षद्वीप : सूक्ष्म क्रस्टेशियन
11.	पर्यावरण संरक्षण निधि
12.	भारत की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना
13.	पहला रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, 2026

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



विश्व का पहला 'थ्री-वे हाइब्रिड बाजरा' : RHB 273



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हैदराबाद के ICRISAT के सहयोग से विश्व के पहले थ्री-वे हाइब्रिड बाजरा 'RHB 273' का विकास किया।



मुख्य बिन्दु:

- नव विकसित बाजरे की यह किस्म ना केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है, बल्कि पैदावार और पोषण में भी परंपरागत किस्मों से बेहतर है।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



- **विकास** : इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), हैदराबाद तथा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर) द्वारा।
- **विमोचन** : RHB 273 का विमोचन 4 जनवरी, 2026 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारत में 25 फसलों की 184 बेहतर किस्मों के साथ किया गया।
- **थ्री-वे हाइब्रिड** : पारंपरिक बाजरा हाइब्रिड के उलट जिनमें दो परेंट्स होते हैं, थ्री-वे हाइब्रिड में तीन परेंट लाइनें होती हैं, जिससे ज़्यादा पैदावार, सूखे को सहने की क्षमता और चारे की बेहतर क्वालिटी जैसी खूबियों को एकीकृत किया जाता है।
- हाइब्रिड बाजरा 'RHB 273' की खेती राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात और हरियाणा के अति-शुष्क क्षेत्रों में की जा सकेगी, जहाँ वार्षिक वर्षा 400 मिमी से कम होती है।
- RHB 273 से तीन राज्यों में 30 स्थानों पर तीन साल की मल्टी-लोकेशन टेस्टिंग से औसतन 2,230 kg/ha उत्पादन हुआ, जो क्षेत्रीय किस्मों की तुलना में लगभग 13 से 27 प्रतिशत ज़्यादा था।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स**:
- **बाजरा उत्पादन में राजस्थान** : प्रथम स्थान पर (44.66 फीसदी की हिस्सेदारी)।
- **राजस्थान में बाजरे की प्रमुख किस्में** : RAJ - 171, RCB - 2, RCB - 911, RHB - 30
- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स** : जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय।
- **बाजरा अनुसंधान केंद्र** : गुड़ामालानी (बाड़मेर)
- राजस्थान में मिलेट्स प्रोत्साहन हेतु राज्य बजट 2022-23 में प्रथम कृषि बजट में घोषित कृषि के 11 मिशनों में 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' लॉन्च किया गया।

--3--

राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा कांस्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर में 'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार' प्रदान किए गए।



मुख्य बिन्दु:

- ये पुरस्कार वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पाँच प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किए गए।
- पाँच प्रमुख श्रेणियाँ :** उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग कार्यालय तथा व्यक्तिगत श्रेणी।
- उपर्युक्त 5 श्रेणियों में कुल 30 संस्थानों एवं व्यक्तियों को तथा 43 अन्य विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



- **सरकारी विभाग वर्ग का पुरस्कार :** सरकारी विभाग वर्ग की जिला कलेक्टर श्रेणी में वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 'प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट' के लिए अलवर जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **सरकारी विभाग वर्ग का पुरस्कार :** अजमेर डिस्कॉम को वाणिज्यिक श्रेणी में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए प्रथम पुरस्कार।
- साथ ही, ऊर्जा मंत्री द्वारा 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के 10 लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप भी प्रदान किया गया।
- जनवरी, 2026 तक राजस्थान 42 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश का अग्रणी राज्य है। (स्रोत - DIPR)

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL)

- **गठन :** अगस्त, 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी (REDA) और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPCL) के विलय से।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत।
- RRECL का उद्देश्य राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024:

- राज्य सरकार द्वारा इस नीति की अधिसूचना 04 दिसंबर, 2024 को जारी की गई।
- **नीति की अवधि:** यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है और 29 मार्च, 2029 तक या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित करने तक लागू रहेगी।

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



लक्ष्य:

- नीति का उद्देश्य राज्य में वर्ष 2029-30 तक 1,25,000 मेगावाट (125 गीगावाट) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

125 गीगावाट का विभाजन:

क्रम	उत्पादन का प्रकार	लक्षित क्षमता
1.	सौर (Solar)	90,000 MW
2.	पवन और हाइब्रिड (Wind & Hybrid)	25,000 MW
3.	हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (PSP), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम	10,000 MW

- नोट:** राजस्थान द्वारा परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54,000 मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031-32 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

--6--

IICDEM-2026 में राजस्थान के पार्टनर देश - क्रोएशिया एवं कज़ाख़स्तान

चर्चा में क्यों?

- 'इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट - 2026' (IICDEM-2026) में क्रोएशिया एवं कज़ाख़स्तान राजस्थान के पार्टनर कंट्री (Partner Country) के रूप में भाग ले रहे हैं।



The poster features a dark blue background with white and orange text. At the top left is the 'SOCIAL MEDIA CELL' logo. At the top right is the 'IICDEM-2026' logo. The central text reads 'IICDEM-2026' in a large white font. Below this, the full name of the conference is written in white: 'INDIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEMOCRACY AND ELECTION MANAGEMENT'. At the bottom left, the dates '21st to 23rd January 2026' are displayed next to a calendar icon. At the bottom right, the location 'Bharat Mandapam New Delhi' is shown with a location pin icon. The IICDEM-2026 logo, which includes a globe, is also present at the bottom left.

--7--

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान द्वारा इन देशों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान, संवाद और सहयोग के माध्यम से चुनाव प्रबंधन, मीडिया एंगेजमेंट तथा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई समझ और नवाचार विकसित किए जाएँगे।
- **आयोजन :** नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी, 2026 तक।
- **आयोजक :** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIDEM) के तत्वावधान में।
- **राजस्थान का प्रतिनिधित्व :** मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के नेतृत्व में राजस्थान का 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल।
- **नोट :** राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त : राजेश्वर सिंह।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--8--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>जामुन, सीताफल व आँवला फ्रूट प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर : उदयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उदयपुर के बलीचा मंडी में राज्य के पहले जामुन, सीताफल और आँवला फ्रूट प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया।उद्देश्य : सीताफल, जामुन, आँवला और एलोवेरा जैसे छोटे वन उत्पादों के साथ-साथ मसालों की प्रोसेसिंग करना।इस प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत विकसित किया गया है।
2.	<p>1 फरवरी, 2026 से MedLEaPR सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप राजस्थान में 1 फरवरी, 2026 से मेडिकल लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) के लिए MedLEaPR सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।MedLEaPR का पूरा नाम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।इसका उद्देश्य चोट, आयु निर्धारण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी हस्तलिखित मेडिको-लीगल रिपोर्टों (MLR) को सुव्यवस्थित और डिजिटाइज़ करना है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दक्षता और समन्वय में सुधार हो सके।01 फरवरी, 2026 से राजस्थान के समस्त पुलिस थानों और चिकित्सालयों में हस्तलिखित रिपोर्टों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

3.	<p style="text-align: center;">राजीविका एवं MNIT जयपुर के मध्य MoU</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) एवं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर के मध्य विभिन्न सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्यों के निष्पादन हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।■ MoU का उद्देश्य : राजीविका की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना।■ यह सहयोग अकादमिक विशेषज्ञता एवं जमीनी अनुभवों के समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
4.	<p style="text-align: center;">आदिवासी युवा-आदान प्रदान कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर में 'आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम' के अंतर्गत ओड़िसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी युवा प्रतिभागियों से संवाद किया।■ आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (TYEP) नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।■ इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना, उन्हें विकास के विभिन्न पहलुओं को दिखाना और उनमें एकता की भावना विकसित करना है।
5.	<p style="text-align: center;">राजस्थान इंडस्ट्री एंड SME समिट : जयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">■ 20 जनवरी, 2026 को जयपुर में 'राजस्थान इंडस्ट्री एंड SME समिट' का आयोजन किया गया।■ यह शिखर सम्मेलन SME चैंबर ऑफ इंडिया और मैनुफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

	<ul style="list-style-type: none">■ थीम : "Exploring Emerging Business, Exports, Investment and Collaborations Opportunities" (उभरते व्यवसाय, निर्यात, निवेश और सहयोग के अवसरों की खोज)।■ उद्देश्य : निर्माताओं, SMEs, निर्यातकों, निवेशकों और संबंधित उद्योगों को एक मंच पर लाना।
6.	<p>बालेसर में रेयर अर्थ एलीमेंट्स (REEs) के भंडार</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, जोधपुर जिले के बालेसर में रेयर अर्थ तत्वों (Rare Earth Elements) के बड़े भंडार की खोज हुई है, जिसमें सीरियम भी शामिल है।■ इससे पूर्व पाली के मारवाड़ जंक्शन और बाली में भी सीरियम के भंडार मिले थे।
7.	<p>सविता माली आर्ट इनोवेशन अवॉर्ड : विजय राही</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) में लालसोट (दौसा) निवासी कवि विजय राही को 'सविता माली आर्ट इनोवेशन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।■ जोधपुर की कला-मर्मज्ञ और चित्रकार सविता माली की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य कला, साहित्य और संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्तियों के सम्मान के साथ-साथ उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है।
8.	<p>बर्ड फेस्टिवल (उदयपुर)</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : 15 से 18 जनवरी 2026 तक रामसर साइट मेनार में।■ संस्करण : 12वाँ।■ आयोजक : राजस्थान पर्यटन विभाग और वन विभाग, राजस्थान।



राष्ट्रीय परिदृश्य



104वाँ स्कोच शिखर सम्मेलन, 2026



चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन (CBS) के लिए "स्कोच अवार्ड, 2025" से सम्मानित किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- यह पुरस्कार समारोह "संसाधन विकसित भारत" विषय पर आयोजित 104वें स्कोच शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित किया गया।
- स्कोच अवॉर्ड भारत भर में शासन और विकास में सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और सरकारी एवं निजी संस्थानों को दिया जाता है।
- यह पुरस्कार वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीनी स्तर के कार्यों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
- **सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन:** सी-डॉट का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एक स्वदेशी आपदा एवं आपातकालीन चेतावनी मंच है।
- आपदा चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियों- मौसम के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), बाढ़ के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC), सुनामी/समुद्री घटनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (INCOIS), भूस्खलन के लिए रक्षा भू-सूचना अनुसंधान संस्थान (DGRE) और वन अग्नि के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) को एक एकीकृत मंच पर लाता है।
- **विकास:** टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (C-DOT)।

सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन की विशेषताएँ:

1. यह प्रभावित नागरिकों तक त्वरित सूचना प्रसारण के लिए सरकारी आपातकालीन चेतावनी प्रसार प्लेटफार्मों और देश के दूरसंचार नेटवर्क के मध्य स्वचालित एकीकरण प्रदान करता है।
2. यह 2G, 3G, 4G और 5G तकनीकों को सपोर्ट करता है।
3. यह 21 भारतीय बहुभाषी के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन कार्यकलापों की समग्र दक्षता में सुधार होता है।
4. यह पहल संयुक्त राष्ट्र की 'सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी' (# EW4-All) पहल, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP), कॉल टू एक्शन के अनुरूप है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे (BBNJ) संधि



चर्चा में क्यों?

- 17 जनवरी, 2026 को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता/संधि लागू हो गई है।



मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** यह समावेशी महासागर शासन सुनिश्चित करने वाली पहली महासागर संधि है।
- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता पर समझौता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS), 1982 के तहत अपनाया गया था।

उत्पत्ति:

- वर्ष, 2008:** खुले समुद्रों के अनियंत्रित दोहन की बढ़ती चिंताओं के कारण वार्ता।
- मार्च, 2023:** इस संधि को अंतिम रूप दिया गया।
- सितंबर, 2025:** 60 देशों की स्वीकृति (भारत भी शामिल)।
- जनवरी, 2026:** 80 से अधिक देशों की स्वीकृति।
- Note:** चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्राजील जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने संधि की पुष्टि कर दी हैं तथा अमेरिका की तरह भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं (वर्ष 2024) किंतु घरेलू पुष्टि प्रक्रिया अभी लंबित है।
- लागू:** यह खुले समुद्रों और अंतरराष्ट्रीय समुद्र पर लागू होती है (अनन्य आर्थिक क्षेत्रों; EE2 से परे और किसी एक देश के नियंत्रण से बाहर स्थित समुद्री क्षेत्रों पर लागू)।
- लक्ष्य:** "30 बाय 30": वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागर क्षेत्र के 30% हिस्से का संरक्षण व संवर्धन करना।

■ संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि/BBNJ समझौते के स्तंभ: 4

1. समुद्री आनुवांशिक संसाधन (MGR); संसाधनों का समान बँटवारा।
2. विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकी की क्षमता निर्माण और हस्तांतरण
3. पर्यावरण प्रभाव आँकलन (EIA)
4. क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण (ABMT); समुद्री क्षेत्र संरक्षण

■ BBNJ की प्रमुख विशेषताएँ:

1. यह महासागर की सतह के दो-तिहाई से अधिक हिस्से के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
2. यह समझौता सतत् विकास लक्ष्य-14 (SDG-14) का समर्थन करता है।
3. यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री सीमा समझौते (UNCLOS) के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। (अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल खनन पर वर्ष 1994 तथा सीमावर्ती और अत्यधिक प्रवासी मछली भंडारों पर वर्ष 1995 का संयुक्त राष्ट्र मछली भंडार समझौता)।
4. यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) के एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण करता है।
5. यह समझौता पुनः पुष्टि करता है कि कोई भी राष्ट्र खुले समुद्र या अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र के समुद्री जैविक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।

भारत-UAE संबंध

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा सम्पन्न की।

मुख्य बिन्दु:

यात्रा के मुख्य परिणाम:

- **व्यापार लक्ष्य:** दोनों देश वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना कर \$200 बिलियन से अधिक करने पर सहमत हुए।
- दोनों देश भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कोरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी पहलों के माध्यम से नए बाजारों को बढ़ावा देंगे।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** शांति अधिनियम-2005 के लागू होने के बाद स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और परमाणु सुरक्षा सहित उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी की संभावनाएँ तलाश की जाएँगी।
- **डिजिटल/डेटा दूतावास की स्थापना:** डिजिटल दूतावास एक विदेशी केन्द्र होता है, जहाँ कोई देश अपना महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा संग्रहित करता है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों, प्राकृतिक आपदाओं, भू-राजनीतिक संघर्षों के विरुद्ध डिजिटल निरन्तरता व सम्प्रभुता सुनिश्चित करना है।
- **AI और तकनीक:** AI इंडिया मिशन के तहत एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर के लिए सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- **ऊर्जा आपूर्ति:** ADNOC गैस द्वारा HPCL को 10 वर्षों के लिए 0.5 MTPA LNG की आपूर्ति हेतु बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गये।
- **नोट:** UAE लगातार भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC): ब्रिक्स

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की है कि सीमा पार व्यापार, पर्यटन और भुगतान निपटान को सरल बनाने के लिए 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडा में ब्रिक्स केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) को शामिल किया जाए। जिसकी मेजबानी भारत इस वर्ष के अंत में करेगा।

मुख्य बिन्दु:

पृष्ठभूमि:-

- **रियो डी जनेरियो ब्रिक्स घोषणा- 2025:-** इसमें सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच अंतरसंचालनीयता पर बल दिया गया। भारत लंबे समय से अपने डिजिटल रुपये के माध्यम से डिजिटल भुगतान एकीकरण की वकालत करता रहा है, जिसका परीक्षण पहले ही ऑफलाइन लेनदेन, प्रोग्रामेबल भुगतान और फिनटेक वॉलेट एकीकरण में किया जा चुका है।

प्रस्तावित ब्रिक्स CBDC लिंकेज के उद्देश्य:-

- सीमापार भुगतान को सुगम बनाना।
- डॉलर पर निर्भरता कम करना।
- वित्तीय सम्प्रभुता को सुदृढ़ करना।
- वित्तीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।
- इसमें एक ऐसे डिजिटल रूप से जुड़े पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना की गई जहाँ ब्रिक्स देशों के केन्द्रीय बैंक अपने-अपने CBDC के माध्यम से व्यापार और पर्यटन भुगतानों का निर्बाध रूप से निपटान कर सकते हैं।
- यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह ब्रिक्स सदस्यों के बीच डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का पहला औपचारिक प्रस्ताव होगा, जो वित्तीय सहयोग के एक नए युग का संकेत देगा।

तकनीकी ढाँचा व कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:-

- अन्तरसंचालनीयता मानक
- निगरानी तंत्र, शासन तथा विनियमन
- असमान व्यापार प्रवाह के निपटान का असंतुलन
- साइबर सुरक्षा और गोपनीयता
- तकनीकी सम्प्रभुता संबंधी चिंताएँ

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी - CBDC :-

- यह डिजिटल रूप से जारी की गई वैध मुद्रा है, जिसका मूल्य नकदी और पारंपरिक बैंक जमा के बराबर होता है।
- यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद होती है और सीधे किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है।
- क्रिप्टोकॉर्सेस के विपरीत, CBDC को भुगतान दक्षता, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नियंत्रण में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

दूसरा डॉल्फिन सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

- जनसंख्या अनुमानों को अद्यतन करने तथा आवासों और खतरों का आंकलन करने हेतु प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उत्तरप्रदेश के बिजनौर से दूसरा व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** मार्च, 2025 में गुजरात के गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में पहले दौर की गणना अनुमान के परिणाम जारी करने बाद अब देश में डॉल्फिन के संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तरप्रदेश के बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी एवं मुहाना क्षेत्र में पायी जाने वाली डॉल्फिन का दूसरा व्यापक अनुमान शुरू किया।
- कार्यक्रम का समन्वय :** भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा राज्य वन विभागों और सहयोग संरक्षण संगठनों WWE इंडिया, आरण्यक और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से।

चरण:

- पहला:** बिजनौर से गंगा नदी तक तथा सिंधु नदी क्षेत्र में सर्वेक्षण।
- दूसरा:** ब्रह्मपुत्र तथा गंगा की सहायक नदियों, सुंदरबन और ओडिशा में सर्वेक्षण।
- गंगा नदी डॉल्फिन के अलावा सिंधु नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन की स्थिति का भी आंकलन किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



पिछले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (2021-23) के परिणाम:

- भारत में डॉल्फ़िन की संख्या: 6327
- गंगा, यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली गंगा नदी डॉल्फ़िन और व्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फ़िन की अपेक्षाकृत कम संख्या शामिल है।

- सर्वाधिक डॉल्फ़िन वाले राज्य: उत्तरप्रदेश > बिहार > पश्चिम बंगाल > असम

प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन:

- लॉन्च: 15 अगस्त, 2020
- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- उद्देश्य: पर्यावास क्षरण, प्रदूषण, आकस्मिक शिकार और जल प्रवाह परिवर्तन जैसे खतरों से निपटते हुए भारत में डॉल्फ़िन का संरक्षण व सम्बर्द्धन करना।
- अवधि: 10 वर्ष

-:20:-

लक्षद्वीप : सूक्ष्म क्रस्टेशियन

चर्चा में क्यों?

- लक्षद्वीप के कवारत्ती लैगून में खोजे गए एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन को औपचारिक रूप से एक नए जीनस और प्रजाति के रूप में नामित किया गया है।

- **नाम :** इंडियाफोन्टे बिजोई।

मुख्य बिन्दु:

परिचय:

- **सूक्ष्म क्रस्टेशियन:** इंडियाफोन्टे बिजोई एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन (कोपेपोड) है जो हार्पेक्टिकोइडा गण के अंतर्गत लाओफोर्टिडी परिवार का सदस्य है।
- यह छोटे अकशेरुकी जीव है जो जलीय तलछट में रहते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है (मीयोफौना)।
- इंडियाफोन्टे बिजोई जो लक्षद्वीप के कवारत्ती लैगून में पाया गया था।
- यह प्रवाल से समृद्ध, उथला लैगून पारिस्थितिकी तंत्र (कवारत्ती लैगून) है।
- **सूक्ष्म क्रस्टेशियन का नामकरण:** इंडियाफोन्टे (भारत के संदर्भ में) बिजोई (प्रसिद्ध भारतीय समुद्री वैज्ञानिक एस. बिजोई नंदन के सम्मान में)।
- ज्ञात लाओफोर्टिडी वंश से अलग रूपात्मक लक्ष्यों के कारण इसे नए वंश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सूक्ष्म क्रस्टेशियन:

- **शरीर:** अर्ध बेलनाकार, पृष्ठीय अधरीय रूप से चपटा, मध्य भाग चौड़ा व पश्च भाग पतला होता है।
- एंटीना उपांग जो तलछटी जीवन के लिए अनुकूलित विशेष अंग है।

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



- **महत्त्व:** पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के प्रतीक, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, शैवाल का भक्षण तथा जलीय खाद्य जालों का आधार बनाते हैं।
- यह प्रदूषण, तेल रिसाव, भारी धातुओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
- इनका उपयोग जलीय कृषि या मत्स्य पालन में किया जा सकता है।
- यह ओमेगा-3 फैटी एसिड (इकोसापेंटेनोइक एसिड, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड) का उत्पादन और रूपांतरण करते हैं, जो मछली और शंख के विकास के लिए आवश्यक है।



-:22:-

पर्यावरण संरक्षण निधि

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम-2026 अधिसूचित किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** पर्यावरण संरक्षण निधि के उपयोग में सुधार करना।
- **विधिक स्वरूप:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत गठित तथा यह राशि भारत के लोक लेखा में जमा की जाती है।
- **निधि के स्रोत:** इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम-1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम-1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत वसूले गए जुर्माने जमा होते हैं।
- **आवंटन:** 75 प्रतिशत धनराशि राज्यों को तथा 25 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार के पास रहती है।
- **निधि का उपयोग:** पर्यावरण निगरानी नेटवर्क की स्थापना, प्रदूषण स्थलों की सफाई, पर्यावरण संबंधी प्रौद्योगिकी में शोध-अनुसंधान हेतु।
- **निगरानी:** इसका प्रबंधन परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाता है। इसका ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है।
- **संस्थाओं का क्षमता संवर्धन:** इस निधि का उपयोग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसी विनियामक संस्थाओं को मजबूत बनाने में भी किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

भारत की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना

चर्चा में क्यों?

- भारत की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ में शुरू की गई।

मुख्य बिन्दु:

अतिरिक्त जानकारी:-

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय + राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान + अण्डमान-निकोबार प्रशासन

उद्देश्य:-

- खुले समुद्र में मछलीपालन के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल की ओर संक्रमण।
- पारंपरिक तटीय मछली पकड़ने पर दबाव कम करना।
- स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए स्थाई आजीविका सृजन।

अण्डमान सागर:-

- **अवस्थिति:** सीमांत, उत्तरी-पूर्वी हिन्द महासागर।
- **रणनीतिक महत्त्व :** यह 10 चैनल तथा 6 चैनल जैसे प्रमुख चोक पॉइन्ट को नियंत्रित करता है, जो मलक्का जलडमरू के माध्यम से होने वाले वैश्विक व्यापार के 25% के लिए महत्त्वपूर्ण है।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

पहला रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, 2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत द्वारा पहला रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स (RNI), 2026 लॉन्च किया गया है जिसमें, भारत ने वैश्विक स्तर पर 11 वाँ स्थान हासिल किया है।

मुख्य बिन्दु:

- लॉन्च:** 19 जनवरी, 2026 को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा।
- परिचय:** यह भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक है जो देशों का मूल्यांकन पारंपरिक शक्ति या GDP केंद्रित मापदंडों के बजाय जिम्मेदार शासन के आधार पर करता है।
- विकास:** विश्व बौद्धिक फाउंडेशन (WIF) के तत्वावधान में।
- सहयोग:** जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय + IIM मुंबई + डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से।
- शामिल देश:** 154 देश।
- मूल्यांकन मापदंड:** 4 स्तंभों पर आधारित-
 - नैतिक शासन।
 - सामाजिक कल्याण और समावेशिता।
 - पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी और स्थिरता।
 - वैश्विक उत्तरदायित्व और सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय आचरण।

Daily Current Affairs

Date : 21 January, 2026



वर्ष 2026 की RNI रैंकिंग:

रैंक	देश
1 st	सिंगापुर
2 nd	स्विट्जरलैंड
3 rd	डेनमार्क
4 th	साइप्रस
5 th	स्वीडन

- **भारत का प्रदर्शन:** रैंक-16 (कुल स्कोर; 0.5515), जो दक्षिण कोरिया (21), थाइलैंड (24) और किर्गिस्तान (22) से अधिक है।
- भारत, एशिया का शीर्ष राष्ट्र है।
- **अंतिम 154वें स्थान पर:** मध्य अफ्रीकी गणराज्य (कुल स्कोर; 0.35715)
- शीर्ष 10 देशों में 9 यूरोपीय देश शामिल है।

--:26:--